2. Talcher Valley Coalfields—2558 (excluding Gopalpur).

(b) Affected families are paid compensation for the land acquired as per the provisions of law. Jobs and/or rehabilitation benefits are provided to the land oustees and their kith and kin as per the guidelines issued by the Government of Orissa.

(c) and (d) As informed by company, there is no such case pending with the management of the company.

पश्चिमी बंगाल बिजली विकास निगम लिमिटेड को घटिया कोयले की आपूर्ति किया जाना

1369. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तापीय विद्युत संयंत्रों को अपर्याप्त एवं घटिया कोयलों की आपूर्ति किये जाने के कारण विद्युत उत्पादन निरन्तर प्रभावित होता रहा है;

(ख) क्या कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा पश्चिमी बंगाल बिजली विकास निगम लि० के विभिन्न संयंत्रों को घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति होती रही है;

(ग) उपर्युक्त संयंत्रों को कोयले की 45 प्रतिशत आपूर्ति करने की जिम्मेदारी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की है और आपूर्ति किये गये कोयले में 55 प्रतिशत राख होती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने विद्युत संयंत्रों को समय पर अच्छी किस्म के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) तापीय विद्युत संयंत्रों को कुल मिलाकर पर्याप्त मात्रा में तथा सहमति हुई गुणवत्ता में जिसके लिये उनके बायलर को अभिकल्पित किया गया है, की आपूर्ति की गई है। आमतौर पर गुणवत्ता संबंधी शिकायतें प्राप्त होती हैं, जो विद्युत गृहों को आपूर्ति किये जा रहे कोयले में बाह्य सामग्री की विद्यमानता तथा कोयले की बड़े आकार में आपूर्ति होने के संबंध में होती हैं, इन शिकायतों पर प्रत्येक मामले में गुणावगुण आधार पर जांच की जाती है तथा उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को कम करने के लिये उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं।

(ख) और (ग) कोलाघाट तापीय विद्युत संयंत्र (के०टी०पी०पी०), जो कि पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लि० (डब्ल्यू०बी०पी०डी०सी०एल०) का एक मात्र संयंत्र है, महानदी कोलफील्ड्स लि०, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० तथा भारत कोकिंग कोल लि० से कोयला की आपूर्ति प्राप्त करता है। कोल इंडिया लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोलाघाट तापीय विद्युत संयंत्र से प्राप्त विश्लेषण के परिणामों के अनुसार कोयले में राख के तत्व 35% तथा 38% सीमा तक की रेंज में होने की पुष्टि करते हैं। सितम्बर-अक्तूबर, 1995 की अवधि के दौरान कोलाघाट तापीय विद्युत संयंत्र में स्थापित क्षमता का 105% विद्युत उत्पादन का रिकार्ड हासिल किये जाने की सूचना मिली है।

(घ) और (ङ) विद्युत गृहों को कोयले का प्रेषण किए जाने की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और कों०इं०लि० तथा रेलवे द्वारा उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं।

कृषि उत्पादों के निर्यात से आय का सृजन

1370. **श्री अजीत जोगी:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय कृषि उत्पादों के निर्यात से राज्य-वार कितनी आय होती है और आगामी तीन वर्षों में कितनी आय होने का अनुमान है;

(ख) कृषि संबंधी निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से मूलभूत ढांचा तैयार करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए पूंजी निवेश संबंधी दिए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि-उत्पादों के निर्यात हेतु प्रस्तावित प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) राज्य-वार निर्यात के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि-जन्य और संबद्ध उत्पादों (काफी, चाय, कपास और समुद्री उत्पादों को छोड़कर) के कुल निर्यात की कीमत नीचे दी गयी है:—

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपये में)
1992-93	5686.81
1993-94	7532.99
1994-95	7049.05
1995-96 (अगस्त, 1995 तक)	3625.77

(स्रोत: डी०जी०सी०आई एंड एस० कलकत्ता)

वर्ष 1991-92 कीमतों पर आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) की शेष अवधि के दौरान उपरोक्त कृषि-जन्य वस्तुओं के लिए निम्नलिखित निर्यात का अनुमान लगाया गया है:—

वर्ष	निर्यात अनुमान (करोड़ रु० में)
1995-96	7497
1996-97	8321

(ख) तथा (ग) ढांचागत सुविधाओं के विकास की एक योजना के तहत सरकार पात्र निर्यातकों को निम्नलिखित के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है:— (1) विशेषीकृत परिवहन इकाइयों को खरीदने के लिए (2) पूर्व-प्रशीतन सुविधाओं की स्थापना के लिए (3) फसल पश्चात् रख-रखाव हेतु यांत्रिकी स्थापित करने के लिए (4) निर्यात के लिए कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए वाष्प उष्मा उपचार/प्रधूमन/छटाई मशीन लगाने के लिए (5) निर्यात उद्देश्य के लिए हवाई-अड्डों/बंदरगाहों पर प्रशीतन भंडार स्थापित करने के लिए (6) भंडारगृहों के निर्माण ग्रेडिंग और छटाई केन्द्रों की स्थापना के लिए सहकारी समितियों/संगठनों को सहायता देना।

निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य प्रस्तावित प्रोत्साहन हैं—अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेताओं की बैठकें आयोजित करना, बाजार विकास अभियान आयोजित करना, उत्पाद विकास में सहायता, पैकेजिंग और गुणवत्ता प्रमाणन, इत्यादि में सुधार।

Import of coal for Visakhapatnam Steel Plant

1371. SHRI MOHAN BABU: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to import coal for Visakhapatnam Steel Plant;

(b) if so, the reasons for the import;

(c) whether coal from Andhra Pradesh is not suitable; and

(d) if so, details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) Yes, Sir. The Visakhapatnam Steel Plant is importing low ash content coking coal to bridge the gap between the requirement and the indigenous availability and to improve the quality of overall blend for technical reasons.

(c) and (d) Coal being produced in Andhra Pradesh by the Singareni collieries Company Ltd. (SCCL) cannot be used for metallurgical purposes. Such coal can only be used for steam raising purposes owing to its non-coking coal nature.

Projects Implementations

1372. SHRI SATISH AGARWAL:
SHRI RAMDAS AGARWAL:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government has seen news-item in 'Indian Express' dated 24th November, 1995 captioned "Government package likely to expedite project implementation" and the details thereof;

(b) whether this issue was recently studied by a Group of Ministers;

(c) if so, whether the Department of Programme Implementation have initiated action in this regard; and

(d) total expenditure sanctioned; spend till date and balance left/funds available during 1995-96 in respect of each project and details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BALRAM SINGH YADAVA): (a) Yes Sir.

(b) and (c) A Group of Ministers was set up under the chairmanship of Dy. Chairman, Planning Commission to suggest specific measures to be taken to reduce delays on account of various factors and expedite implementation of the projects. The Group has since submitted its report which is under the consideration of the Government.